कानपुर, शनिवार, 18 अप्रैल, 2026
वर्ष: 03, अंक: 97, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

साप्ताहिक समाचार पत्र

इनसाइड >1.16 करोड़ की वसूली की तैयारी..>Pg10

रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने दुकानदार को मार डाला!...>Pg03

मूल्य: 2 ₹

बिना इंटरनेट आधार वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी-ओटीपी से मुक्ति, डिजिटल सिग्नेचर से सुरक्षा मजबूत

अब QR बताएगा असली पहचान

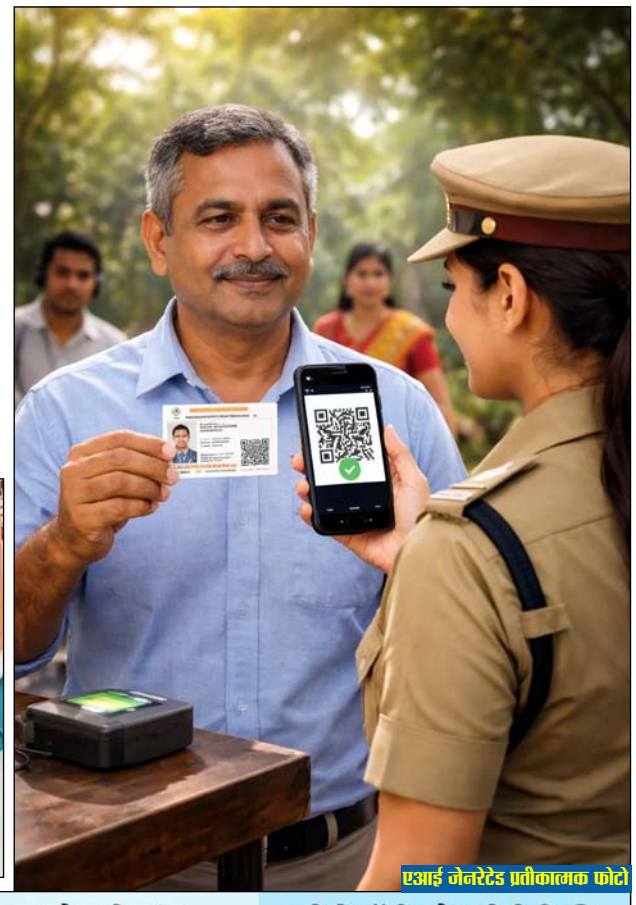

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। पहचान सत्यापन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसके तहत अब आधार आधारित वेरिफिकेशन पूरी तरह डिजिटल, तेज और अधिक सुरक्षित बनने जा रहा है। नई ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन प्रणाली के लागू होने से लोगों को अब आधार की फोटोकॉपी देने या ओटीपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। क्यूआर कोड, ई-आधार या मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यक्ति अपनी पहचान तुरंत सत्यापित करा सकेगा, वह भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, इस नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें आधार धारक की गोपनीयता को प्राथमिकता दी गई है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह व्यक्ति की सहमति पर आधारित होगी और केवल आवश्यक जानकारी ही साझा की जाएगी। इससे व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण बना रहेगा और दुरुपयोग की आशंका काफी कम हो जाएगी।

नई प्रणाली के तहत अब कार्यालयों, होटलों और आवासीय सोसायटियों में प्रवेश के समय क्यूआर कोड स्कैन कर पहचान सुनिश्चित की जाएगी। स्कैन के बाद दस्तावेज में मौजूद जानकारी का मिलान डिजिटल सिग्नेचर से होगा, जिससे यह प्रमाणित हो सकेगा कि दस्तावेज असली है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है, इसलिए नेटवर्क की समस्या भी इसमें बाधा नहीं बनेगी।

सरकारी दफ्तरों, डेटा सेंटर और निजी संस्थानों में इस तकनीक के उपयोग से सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर फेस वेरिफिकेशन जैसी अतिरिक्त तकनीकों का उपयोग कर व्यक्ति की वास्तविक उपस्थिति भी सुनिश्चित की जा सकेगी। वहीं, रेजिडेंशियल सोसायटी में मेहमानों, डिलीवरी कर्मियों और घरेलू सहायकों की एंट्री अब अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से दर्ज हो सकेगी। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में भी इसका असर दिखाई देगा। बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में केवाईसी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल हो जाएगी। डिजिटल सिग्नेचर आधारित सत्यापन से मैनुअल जांच और अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत कम होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

यह पूरी व्यवस्था तीन प्रमुख स्तंभों आधार धारक, सत्यापन करने वाली संस्था और यूआईडीएआई पर आधारित है। कानूनी रूप से भी यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है और आधार अधिनियम 2016, आईटी एक्ट 2000 तथा डिजिटल डेटा संरक्षण कानून के तहत लागू की गई है। प्रशासन ने सभी संस्थानों से इस नई प्रणाली को अपनाने की अपील की है, ताकि पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ावा मिल सके। कुल मिलाकर, यह बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो न केवल पहचान सत्यापन को आसान बनाएगा, बल्कि नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा को भी सुदृढ़ करेगा।

आम लोगों को कितना फायदा?

नई व्यवस्था से आम नागरिकों को सबसे बड़ा लाभ सुविधा और समय की बचत के रूप में मिलेगा। बार-बार दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने या ओटीपी का इंतजार करने की जरूरत खत्म होगी। खासकर ग्रामीण और नेटवर्क कमजोर क्षेत्रों में यह प्रणाली बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। हालांकि, डिजिटल साक्षरता की कमी वाले लोगों के लिए शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं।

तकनीक पर निर्भरता की चुनौती

ऑफलाइन होने के बावजूद यह प्रणाली पूरी तरह तकनीक आधारित है। ऐसे में छोटे संस्थानों में स्कैनिंग और सत्यापन उपकरणों की उपलब्धता तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है।

संस्थानों की जिम्मेदारी बढ़ी

जहां यह सिस्टम संस्थानों के लिए तेज और आसान वेरिफिकेशन का रास्ता खोलता है, वहीं उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। उन्हें सही तरीके से क्यूआर स्कैनिंग, डेटा हैंडलिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या डेटा लीक की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

गोपनीयता बनाम सुविधा

नई व्यवस्था में सुविधा के साथ गोपनीयता का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पहले जहां पूरी आधार कॉपी साझा करनी पड़ती थी, वहीं अब सीमित जानकारी ही साझा होगी। हालांकि, संस्थानों की डेटा हैंडलिंग क्षमता पर लगातार निगरानी जरूरी रहेगी।

फर्जीवाड़े पर प्रभावी लगाम?

डिजिटल सिग्नेचर और क्यूआर आधारित सत्यापन से फर्जी दस्तावेजों पर काफी हद तक रोक लगेगी। फिर भी, साइबर सुरक्षा के नए जोखिमों को देखते हुए सिस्टम को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानक मजबूत बने रहें।

भविष्य में और क्या बदलाव संभव?

यह बदलाव डिजिटल पहचान के क्षेत्र में एक बड़े ट्रांजिशन का संकेत है। आने वाले समय में फेस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक और एआई आधारित पहचान प्रणाली को और व्यापक बनाया जा सकता है। साथ ही, अन्य सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्रों में भी इसी तरह की ऑफलाइन डिजिटल वेरिफिकेशन तकनीकों के विस्तार की संभावना है, जिससे पूरी पहचान व्यवस्था और अधिक आधुनिक व सुरक्षित हो सकेगी।

8 करोड़ रुपये से एएनडी कॉलेज का होगा कायाकल्प

नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। नगर निगम के नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय (ए0एन0डी0 कालेज) व तिलक नगर बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कॉलेज के कायाकल्प से लेकर जनगणना 2027 की तैयारियों तक कई अहम निर्देश दिए गए।

नगर आयुक्त ने ए0एन0डी0 कालेज की भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए बताया गया कि यहां वर्तमान में 1065 छात्राएं अध्ययनरत हैं, जबकि 50 शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। कॉलेज के विकास के लिए मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत 8.00 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।

इसके अंतर्गत 2 लेक्चर थियेटर, 12 स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी का नवीनीकरण, कंप्यूटर लैब, पेयजल व्यवस्था, पार्किंग व गार्ड रूम समेत पूरे कॉलेज के रेनोवेशन का कार्य शामिल है।

नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर कार्य जल्द शुरू कराया जाए।

निरीक्षण के दौरान कॉलेज की क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई।

प्राचार्या द्वारा आंधी-तूफान से दीवार टूटने की जानकारी देने पर नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि 20.04.2026 से पहले मरम्मत कार्य हर हाल में पूरा कराया जाए।

जनगणना 2027 प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा

ऑडिटोरियम की हालत खराब, बनेगी नई

कार्ययोजना-कॉलेज के ऑडिटोरियम की जर्जर स्थिति पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। सीटें टूटी हुई, बालकनी व फॉल सीलिंग क्षतिग्रस्त पाए जाने पर मुख्य अभियंता को निर्देश दिए गए कि तत्काल निरीक्षण कर रेनोवेशन की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

स्वराज इंडिया X क्लूसिव

सफाई व आवारा पशुओं पर सख्ती

कॉलेज परिसर के बाहर कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की मौजूदगी पर नगर आयुक्त ने तत्काल सफाई कराने और पशुओं को पकड़कर काजी हाउस भेजने के निर्देश दिए।

जनगणना 2027 प्रशिक्षण की समीक्षा

तिलक नगर बालिका विद्यालय में चल रहे जनगणना 2027 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया गया। यहां 200 के सापेक्ष 189 प्रगणक/सुपरवाइजर उपस्थित पाए गए। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि गर्मी को देखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया जाए और सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रखी जाएं।

बालिका विद्यालय में बढ़ेंगी सुविधाएं

तिलक नगर बालिका विद्यालय में 600 छात्राओं के अध्ययनरत होने की जानकारी मिली। विद्यालय में वाटर कूलर, कंप्यूटर, शौचालय मरम्मत, सीसीटीवी सिस्टम, स्मार्ट क्लास और रंगाई-पुताई की कमी पाई गई।

नगर आयुक्त ने जोनल अभियंता को तत्काल निरीक्षण कर सभी कमियों को दूर करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय के बाहर खड़े वाहनों को हटाने और ग्रीनरी व ग्रिल लगाकर सौंदर्यीकरण कराने के निर्देश भी दिए।

केडीए सील के बाद भी जारी रहा अवैध निर्माण

शिकायत के बावजूद नहीं रुका काम, पीड़ित ने प्राधिकरण पर लापरवाही का लगाया आरोप

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने का मामला सामने आया है, जिससे केडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जोन 3 के किदवई नगर क्षेत्र के ब्लॉक स्थित भूखंड संख्या 128/15 बी में अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा 30 मार्च 2026 को आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराते हुए अवैध निर्माण की जानकारी दी गई थी।बताया गया कि केडीए के सक्षम अधिकारियों द्वारा 15 अप्रैल 2026 को उक्त निर्माण को सील करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य रुक नहीं सका।

आरोप है कि सीलिंग की कार्रवाई के बाद भी निर्माण जारी रहा, जो प्राधिकरण की कार्यवाही को लेकर गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।शिकायतकर्ता विवेक शुक्ला ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

साथ ही कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता रहेगा।अब देखना यह होगा कि केडीए इस प्रकरण को कितनी गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल यह मामला प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है।

गड्ढों के जाल में शहीद मेजर सलमान बस अड्डा का 'स्वागत द्वार'

रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही, फिर भी मुख्य प्रवेश द्वार पर बदहाल सड़कें हादसे का बढ़ता खतरा, जिम्मेदार खामोश

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही के बावजूद सड़क मरम्मत नहीं
- बारिश में गड्ढे बनते हैं 'छुपा खतरा', दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी
- वाहन चालकों को हो रहा आर्थिक नुकसान, संचालन प्रभावित
- कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभागों की अनदेखी
- के 'स्मार्ट सिटी' दावों पर उठ रहे सवाल

कानपुर। शहर के सबसे व्यस्ततम परिवहन केंद्रों में शुमार शहीद मेजर सलमान बस अड्डा (टाटमिल चौराहा) इन दिनों अपनी जर्जर सड़कों के कारण सुर्खियों में है। बस अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार पर फैले गहरे खड्डे और उखड़ी सड़कें न केवल यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन रही हैं, बल्कि बड़े हादसे को भी खुला न्योता दे रही हैं।

प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर जैसे ही वाहन प्रवेश करते हैं, उन्हें उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरना पड़ता है। गहरे गड्ढों में फंसकर वाहन अचानक झटके खाते हैं, जिससे सवारियों को चोट लगने का खतरा बना रहता है। हालात तब और भी खराब हो जाते हैं जब बारिश या जलभराव के चलते ये गड्ढे नजर ही नहीं आते। ऐसे में बाइक सवार, ऑटो चालक और पैदल यात्री सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम और संबंधित विभागों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यात्रियों में भी इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि शहर के इतने महत्वपूर्ण बस अड्डे का मुख्य द्वार ही अगर इस हाल में रहेगा, तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है।

बस चालकों की परेशानी भी कम नहीं है। उनका कहना है कि खराब सड़क के कारण वाहनों के पुर्जे जल्दी खराब हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही बसों के संचालन में देरी भी हो रही है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता की पोल खोलती है। जहां एक ओर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रमुख परिवहन केंद्रों की ऐसी बदहाली जमीनी हकीकत बयां कर रही है। अगर जल्द ही इन खड्डों की मरम्मत नहीं कराई गई, तो कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है।

रहस्य में घिरा लापता युवक

'श्रेया' की कॉल ने बढ़ाई उलझन

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- दोस्तों संग निकला था युवक फतेहपुर टोल तक मिला सुराग पुलिस कई एंगल से जांच में जुटी

कानपुर। चकेरी क्षेत्र के मंगल विहार निवासी एक युवक के रहस्यमय ढंग से लापता होने से हड़कंप मच गया है। युवक बाराबंकी जिले के मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में तैनात था। परिजनों के अनुसार, वह दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर से निकला था, लेकिन इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल सका।

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी फतेहपुर टोल प्लाजा से मिली है, जहां सीसीटीवी फुटेज में युवक की कार के गुजरने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और टोल के आगे-पीछे के मार्गों की निगरानी बढ़ा दी गई है।

जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लापता होने से ठीक पहले युवक के मोबाइल पर 'श्रेया' नाम की किसी महिला का कॉल आया था। पुलिस इस कॉल डिटेल को गंभीरता से खंगाल रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि कॉल करने वाली महिला कौन है और उसका इस पूरे मामले से क्या संबंध हो सकता है।

फिलहाल पुलिस हर संभावित एंगल दोस्तों की भूमिका, कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। युवक की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। घटना ने क्षेत्र में चिंता और कौतूहल दोनों पैदा कर दिया है।

रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने दुकानदार को पीट-पीटकर मार डाला!

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

- हनुमंत विहार में दिल दहला देने वाली वारदात, मां की आंखों के सामने बेटे की गई जान, आरोपी हिरासत में

कानपुर। हनुमंत विहार इलाके में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में हुए झगड़े के दौरान एक किराना दुकानदार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि मृतक की बुजुर्ग मां अपने बेटे को बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा।

हनुमंत विहार निवासी 40 वर्षीय विकास उर्फ सोनू अपनी मां माया देवी के साथ रहता था और घर पर ही किराने की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी पत्नी करीब 11 साल पहले उसे छोड़कर जा चुकी थी, जिसके बाद वह अपनी मां का एकमात्र सहारा था। शुक्रवार दोपहर सोनू घर पहुंचा और बताया कि उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया है। उसने पास में रहने वाले एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे कपिल यादव पर शक जताया। इसी दौरान कपिल वहां से गुजरा तो सोनू ने उससे मोबाइल लौटाने की बात कही। आरोप लगते ही कपिल भड़क उठा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गया।

देखते ही देखते विवाद हिंसा में बदल गया और कपिल ने सोनू के चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर लगा, जिससे वह असंतुलित होकर सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह सब उसकी मां की आंखों के सामने हुआ, जो लगातार बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी नहीं रुका। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। आनन-फानन में परिजन और पड़ोसी सोनू को पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कपिल यादव को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मारपीट के दौरान गिरने से मौत की बात सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परिजनों के मुताबिक, कपिल अक्सर सोनू से शराब के लिए पैसे मांगता था और दोनों ने घटना वाले दिन भी साथ बैठकर शराब पी थी। इसी दौरान मोबाइल गायब होने पर विवाद शुरू हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ। इस हृदयविदारक घटना ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। खास बात यह है कि जिस दिन सोनू की मौत हुई, उसी दिन उसकी शादी की सालगिरह भी थी। बहनों रजनी और नीलम का रो-रोकर बुरा हाल है। कोरोना काल में पिता की मृत्यु और चार साल पहले एक भाई के निधन के बाद अब सोनू ही मां का आखिरी सहारा था, जो इस घटना में छिन गया।

एल्डिको टाउनशिप में अब 'टोटी चोरी'!

» विला A-28 से बाथरूम-किचन की टोटियां गायब

» CX04 और CX-05 के बाद अब A-28 विला में भी चोरी

» रहवासियों में दहशत, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

गेटेड सोसाइटी में लगातार चोरी की घटनाएं, सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर।आईआईटी के पीछे स्थित एल्डिको जवाहरपुरम टाउनशिप में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गेटेड सोसाइटी होने के बावजूद अब यहां घरों के अंदर से टोटियां तक चोरी होने लगी हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल

खास खबर

गई है। एल्डिको जवाहरपुरम टाउनशिप में जिस तरह चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वह सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। अब जरूरत है कि प्रबंधन और प्रशासन दोनों मिलकर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि रहवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ताजा मामला विला ए-28 का है। राजीव अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 17/04/2026 को जब उन्होंने एल्डिको के प्रतिनिधि पंकज गुप्ता की मौजूदगी में अपने विला को खोला, तो बाथरूम और किचन में लगी सभी टोटियां (वॉटर टैप) गायब मिलीं। इस घटना की सूचना तत्काल एल्डिको प्रबंधन को दे दी गई।

लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं

इससे पहले CX04 विला में ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई थी, वहीं दिनांक 05/04/2026 को CX-05 विला में भी ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया था। लगातार हो रही घटनाओं ने पूरे टाउनशिप के रहवासियों को भयभीत कर दिया है।

गेटेड सोसाइटी का ये हाल?

स्थानीय निवासी मनीष पांडे, संदीप शुक्ला और अनिल कनोडिया का कहना है कि जब गेटेड सोसाइटी में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो आम इलाकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

रहवासियों का कहना है कि टाउनशिप में न पर्याप्त गार्ड हैं, न सीसीटीवी की प्रभावी निगरानी और न ही आने-जाने वालों की सख्त जांच। इसी का फायदा उठाकर चोर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

प्रबंधन की चुप्पी, बढ़ा आक्रोश

बार-बार शिकायतों के बावजूद एल्डिको प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे रहवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वे अब प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारी इन घटनाओं पर कार्रवाई की बजाय मजाक बना रहे हैं. इंडिगो टाउनशिप में चल रही मनमानी से लोग नाराज हैं.

rajiv agra... 3:33 pm
to Karunanidhi...

Dear Karunanidhi,

I am Rajiv Agrawal and resident of Villa no-A28 in ELDECO, today I opened our villa in presence of Mr. Pankaj Gupta ji of Eldeco and found all the tabs missing from the bathroom and kitchen area also. I have been intimate to ELDECO representative mr. Mridul Panday ji. My mobile no is under for further communication if needed to any residents of ELDECO County

Rajiv Agrawal-7617016711,7985454356

Show quoted text

With Regards,

Rajiv Agrawal (MD)
Agrawal Gases
A.G. Carbonics P.Ltd.
Reg Off : 120 D, Nauriya Khera,
Panki Industrial Area I
Kanpur
Ph.: 0512-2692144, 9839134644

सम्पादकीय

महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक सिर न चढ़े

जैसे कि पहले से कायस लगाए जा रहे थे, शुक्रवार को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। दरअसल, यह बिल देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। राजनीतिक पंडित पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिये जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है, जिससे बिल के पारित होने पर संशय था। वैसा ही हुआ और राजग सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और इसके विरोध में 230 वोट पड़े। आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब दोनों बाकी प्रस्तावित संशोधन बिलों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष ने संसद में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल उठाये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। मगर राजग सरकार ने प्रस्तावित 131वें संविधान बिल 2026 में सीटों में आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की बात कही थी। दरअसल, विपक्ष इस संशोधन बिल की टाइमिंग और आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की शर्त पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 33 फीसदी आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ही लागू करना चाहिए। विपक्ष परिसीमन से उपजी विसंगतियों और दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को तरजीह देने की बात करता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बिल का मकसद महिला सशक्तीकरण ही है। जिसके लिये इसके लागू करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की दलील थी कि परिसीमन संविधान सम्मत है और बढ़ती आबादी के बाद सीटों को तार्किक बनाये जाने की जरूरत है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से एससी-एसटी के हितों के पैरोकार होने की दलीलें भी दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर उत्तर-दक्षिण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश की कीमत चुकाने की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये संशोधन दलित व पिछड़े वर्गों के हित में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाये गए कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना कितना न्यायसंगत है। इसके लिये नये जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने की तार्किकता को लेकर भी सवाल उठाया।

उप्र की राजनीति में क्या उपेक्षित महसूस कर रहा है 'सामान्य' वर्ग?

भारतीय राजनीति इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस बदलते दौर में उप्र की बात करें तो हाल के वर्षों में PDA (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) का मॉडल व नारा समाजवादी पार्टी की राजनीति के केंद्र में मजबूती से उभरा है। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रचारित PDA फॉर्मूला स्पष्ट रूप से वोट बैंक साधने की एक सामाजिक गणित है। PDA के सम्बन्ध में बात करें तो यदि P से पिछड़ा, D से दलित और अल्पसंख्यक ही दल की प्राथमिकता है, तो यह प्रश्न उठना अनिवार्य हो जाता है कि सामान्य जाति का स्थान इस ढांचे में है कहाँ ?

लेखक-श्याम सिंह पंवार (वरिष्ठ पत्रकार)
पूर्व सदस्य प्रेस काउंसिल आफ इंडिया

वहीं राजनीति में जब कोई दल अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देता है, तो वह अनजाने में ही अन्य वर्गों को यह संदेश दे देता है कि उनकी (सामान्य जाति की) आवश्यकता वोट बैंक के रूप में शायद अब प्राथमिकता में नहीं रही। शायद यही संदेश समाजवादी पार्टी ने दिया है।

अब भाजपा की बात करें तो भाजपा का नारा सबका साथ.. का विरोधाभास किसी से छुपा नहीं दिख रहा। उसने भी सामान्य जाति को किनारे पर ही रखा है। हालांकि सामान्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर झुकाव रखता रहा है। लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने सामान्य जाति के विश्वास को भी झकझोरा है।

Sc/St उत्पीड़न बिल का समर्थन करने के बाद यूजीसी इक्विटी एक्ट को सामान्य जाति के परिवारों पर थोप देना अनेक सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एस्ट/एस्स उत्पीड़न कानून को मूल स्वरूप में बहाल करने के फैसले ने सामान्य वर्ग के युवाओं में असंतोष पैदा किया था। वहीं यूजीसी नियमों में बदलाव और लेटरल एंट्री जैसे विषयों पर सरकार के रुख ने शिक्षित सामान्य वर्ग के बीच यह धारणा प्रबल की है कि मेरिट की तुलना में राजनीतिक विवशताओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है।अतीत में अगर नजर डालें और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की बात करें तो उसकी प्राथमिकता में Sc/St वर्ग रहा, औपचारिकता में अन्य वर्ग।

इसी एकतरफा नजरिए के चलते अन्य वर्गों का मोह भंग हो गया था। वहीं सामान्य जाति, बसपा के एजेंडा से सदैव किनारे पर रही। दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने की बात किसी से छुपी नहीं है।

शायद इसी लिए वो सत्ता से कई दशकों वंचित है। उप्र में वर्तमान परिस्थितियों में? जब प्रमुख विपक्षी दल (सपा) जातिगत जनगणना और विशिष्ट समूहों की बात कर रहा हो, और सत्ताधारी दल (भाजपा) भी अपनी नीतियों में सामाजिक संतुलन साधने के चक्कर में सामान्य वर्ग के हितों को दरकिनार कर रहा हो अथवा अनदेखा कर रहा हो, तो एक राजनीतिक शून्य पैदा होता है।इस शून्य को भरने के लिए नया विकल्प खोजने की चर्चा तर्कसंगत लगती है। सामान्य वर्ग के लिए चुनौती यह है कि वे संख्या बल में कम होने के बावजूद आर्थिक और बौद्धिक रूप से समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहें। वहीं यदि वे (सामान्य वर्ग) खुद को राजनीतिक रूप से अनाथ महसूस करते हैं, तो भविष्य में ऐसे संगठनों या दलों का उदय होना सम्भव है जो योग्यता और समान अवसर की बात को अपना मुख्य एजेंडा बनाएं।लोकतंत्र के नजरिए से बात करें तो, किसी भी राजनीतिक गठबंधन का उद्देश्य वंचितों को आवाज देना होता है, लेकिन, जब राजनीति का नामकरण ही विशिष्ट समूहों / वर्गों के आधार पर हो, तो उन वर्गों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा होना लाजिमी है जो इस संक्षिप्तीकरण से बाहर रखे जा रहे हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का PDA मॉडल, एक बड़े व प्रभावी मतदाता समूह को अपने से दूर कर देगा। वहीं, भाजपा को भी यह समझना होगा कि उसके आधार स्तंभ माने जाने वाले वर्ग की अनदेखी उसे भारी पड़ सकती है।

राजनीति केवल जोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह अहसास दिलाने का नाम भी है कि कोई पीछे नहीं छूटा है। उप्र में कांग्रेस व बसपा की राजनीति अभी ढुलमुल व असरहीन दिख रही है। ऐसे में यदि सामान्य वर्ग को लगेगा कि वह अप्रासंगिक हो गया है, तो वह निश्चित रूप से नई राहें तलाशेगा, जिसकी आवश्यकता दिख रही है। कहावत भी है कि,आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।

पुरुषोत्तम द्विवेदी
वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा में संविधान संशोधन बिल का गिरना सतही तौर पर भाजपा के लिए एक राजनीतिक झटका लग सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति के मौजूदा दौर में घटनाओं को केवल परिणामों से नहीं, बल्कि उनके बाद गढ़े गए नैरेटिव से समझना अधिक जरूरी हो गया है। यही वह जगह है जहां भाजपा एक बार फिर अपने विरोधियों से आगे निकलती दिखाई देती है। यह मामला सिर्फ एक बिल के पास या फेल होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक अवसर में बदलने की रणनीति पहले से तैयार दिखती है।

महिला आरक्षण बिल गिरा: भाजपा ने गढ़ लिया नया राजनीतिक नैरेटिव, विपक्ष की जीत भी बन गई चुनौती

भाजपा ने जिस तरह इस बिल को पेश किया, वह अपने आप में एक सोची-समझी चाल थी। यह एक ऐसा दांव था जिसमें चित भी मेरी, पट भी मेरी वाली स्थिति स्पष्ट दिखती है। यदि बिल पास हो जाता, तो भाजपा इसे महिलाओं के सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक सुधारों की ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती। इससे न केवल उसकी राजनीतिक साख मजबूत होती, बल्कि चुनावी लाभ भी सुनिश्चित होता। लेकिन बिल गिरने के बाद भी भाजपा ने इसे हार मानने के बजाय एक नए विमर्श का आधार बना लिया।

अब पूरी रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि इस असफलता को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के रूप में प्रस्तुत किया जाए। भाजपा ने अपनी महिला सांसदों को आगे कर धरना-प्रदर्शन शुरू कराया है, जो एक प्रतीकात्मक कदम भर नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक संदेश है। इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाजपा महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रही है, जबकि विपक्ष ने इसे बाधित किया।

आज के दिन को देश की बहनों और लोकतंत्र के लिए काला दिन बताना भी महज भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक फ्रेमिंग है। इस तरह के शब्द जनता के बीच गहरी छाप छोड़ते हैं और धीरे-धीरे एक धारणा का निर्माण करते हैं।

भाजपा इस धारणा को चुनावी मुद्दे में बदलने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां यह सवाल उठाया जाएगा कि आखिर विपक्ष ने महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण बिल को क्यों रोका।

विपक्ष की स्थिति इस पूरे घटनाक्रम में काफी जटिल हो गई है। संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से उसने भले ही एक जीत हासिल की हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वह इस जीत को प्रभावी ढंग से भुना नहीं पा रहा। भाजपा के आक्रामक रुख और स्पष्ट संदेश के सामने विपक्ष की रणनीति बिखरी हुई नजर आती है। विपक्ष के नेता अपनी जीत पर भले ही संतोष जता रहे हों,

लेकिन जनता के बीच वह इसे सकारात्मक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने में असफल दिख रहे हैं।

दरअसल, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी भी मुद्दे को केवल तथ्यों के आधार पर नहीं छोड़ती, बल्कि उसे भावनाओं, प्रतीकों और जनसंचार के माध्यम से एक व्यापक आंदोलन का रूप देती है। यह पार्टी जानती है कि राजनीति में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। इसलिए वह हर हार को एक नई कहानी में ढालने की कोशिश करती है एक ऐसी कहानी, जिसमें वह खुद को संघर्षशील और विपक्ष को बाधक के रूप में प्रस्तुत कर सके।आने वाले चुनावों के संदर्भ में देखें तो यह मुद्दा भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए यह एक प्रभावी नैरेटिव तैयार कर रहा है, जिसमें भाजपा खुद को उनके अधिकारों की रक्षक के रूप में पेश करेगी।

दूसरी ओर, विपक्ष के लिए यह चुनौती और बढ़ जाती है कि वह इस धारणा को कैसे तोड़े और अपनी स्थिति को स्पष्ट करे।

अंततः यह पूरा घटनाक्रम इस बात का उदाहरण है कि भारतीय राजनीति अब केवल विधायी सफलता या विफलता तक सीमित नहीं रही। यह नैरेटिव, धारणा और जनभावनाओं की राजनीति बन चुकी है। और इस खेल में भाजपा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह न सिर्फ चाल चलने में माहिर है, बल्कि हर परिणाम को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता भी रखती है।

जनगणना की तैयारी तेज, प्रशिक्षण शुरू

बिल्हौर में 384 प्रगणकों को प्रशिक्षण, लापरवाही पर सख्ती

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए तहसील बिल्हौर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार के जनगणना निदेशालय के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार से प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया। यह प्रशिक्षण 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जनगणना से जुड़े सभी कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश और तकनीकी जानकारी दी जा रही है।

प्रशिक्षण के पहले दिन कुल 384 प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को बुलाया गया, जिन्हें 16 फील्ड ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के लिए तहसील क्षेत्र में तीन केंद्र अकाडिया इंटरनेशनल स्कूल, आरपीएस अरौल मकनपुर और

➪ एसडीएम-तहसीलदार ने केंद्रों का किया निरीक्षण, अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश

डीपीएस बिल्हौर निर्धारित किए गए हैं। इन केंद्रों पर जनगणना से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे घर-घर सर्वे, डेटा संकलन, डिजिटल उपकरणों के उपयोग और सटीक जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है।

इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार और तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने प्रशिक्षण केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उन्हें जनगणना कार्य की गंभीरता को समझने और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि

जनगणना एक संवेदनशील और आधारभूत प्रक्रिया है, जिस पर सरकारी योजनाओं और नीतियों की नींव टिकी होती है।

प्रशासन ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना उचित कारण अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ जनगणना अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी नामित कर्मियों को निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

- 17 से 26 अप्रैल तक चलेगा जनगणना प्रशिक्षण
- पहले दिन 384 प्रगणकों को दी गई ट्रेनिंग
- 16 फील्ड ट्रेनर्स द्वारा कराया जा रहा प्रशिक्षण
- तीन केंद्रों पर आयोजित हो रहा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अनुपस्थित कर्मियों पर जनगणना एक्ट के तहत कार्रवाई तय
- अधिकारियों ने कहा जनगणना में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं

जहां बजनी थी शहनाई वहां पसरा मातम

तिलक से चार दिन पहले युवती ने लगाई फांसी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। शादी की तैयारियों के बीच एक परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। बिल्हौर थाना क्षेत्र के डोडवा जमौली गांव में 22 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवती का तिलक चार दिन बाद 20 अप्रैल को होना था, जबकि 7 मई को बारात आनी तय थी।

जानकारी के अनुसार गांव निवासी रमेश गौतम, जो राजमिस्त्री के साथ खेती भी करते हैं, उनकी बेटी शिवानी की शादी तय हो चुकी थी और घर में जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं। शुक्रवार दोपहर रमेश गौतम एक परिचित के अंतिम संस्कार में गए थे। घर पर उनकी पत्नी और बेटी शिवानी मौजूद थीं, जबकि दोनों बेटे बाहर गए थे। इसी दौरान शिवानी ने घर के बाहर बने कमरे को अंदर से बंद कर लिया और पंखे के कुंडे से दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को जब रमेश गौतम घर लौटे तो बेटी के बारे में पूछने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। संदेह होने पर खिड़की से झांककर देखा गया तो शिवानी फंदे से लटकी मिली। यह दृश्य देखते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतरवाया। फोरेंसिक टीम ने मौके से

➪ आगामी 7 मई को आनी थी बारात, घर में चल रही थीं तैयारियां

महिला ने फांसी लगाकर दी जान, 13 साल पहले हुई थी शादी

बिल्हौर (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र के ग्राम मुनौवरपुर में शुक्रवार शाम एक महिला ने कमरे के अंदर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी जितेंद्र राजपूत के अनुसार, मुनौवरपुर निवासी लवली (35) पत्नी हरमोहन ने अपने कमरे में छत के पंखे से साड़ी के सहारे फांसी लगा ली। घटना की जानकारी पुलिस को शाम करीब 7:50 बजे मिली, जिसके बाद तत्काल टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि मृतका की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व हुई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी, वहां अब मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुल के पास बेकाबू होकर बाइक खड्डु में गिरी, युवक की मौत

स्वराज इंडिया ब्यूरो

ककवन (कानपुर)। ककवन थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बिल्हौर-रसूलाबाद मार्ग पर पांडु नदी पुल के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खड्डु में जा गिरी।

जानकारी के अनुसार, कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मुर्रा गांव निवासी वीरेंद्र उर्फ नीलू अपने साढ़ू के घर कुरेह गांव जा रहे थे। रास्ते में पुल

➪ खेती कर परिवार चलाता था युवक, परिवार में मचा कोहराम

के पास अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह खड्डु में जा गिरे। हादसा देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बाहर निकलवाया और एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ककवन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। बताया गया कि वीरेंद्र खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी ज्योति और एक बेटी श्वेता हैं।

थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बाइक के अनियंत्रित होकर खड्डु में गिरने से हादसा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

एक पहल जिंदगी के नाम, 50 यूनिट रक्त कर गया बड़ा काम

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील सभागार में शुक्रवार को आयोजित रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। द लॉयर्स एसोसिएशन बिल्हौर के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में कुल 50 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद सुबह से ही रक्तदाताओं का आना शुरू हो गया। दिनभर चले इस शिविर में अधिवक्ताओं, युवाओं और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। रक्तदान करने वालों में खासा उत्साह रहा और लोगों ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर इस पुनीत कार्य में योगदान दिया।

इस दौरान वक्ताओं ने रक्तदान के

➪ अधिवक्ताओं और युवाओं ने निभाई अहम भूमिका, मानवता की मिसाल पेश

महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह एक ऐसा दान है, जो सीधे किसी जरूरतमंद को जीवन प्रदान करता है। उपजिलाधिकारी ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। आयोजक अधिवक्ता सुशांत मिश्र ने बताया कि शिविर में 50 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जो समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। अंत में आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया।

सेंट्रल स्टेशन पर फर्जी रेलवे अफसर गिरफ्तार, नकली आईडी से झाड़ रहा था रौब

» प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

शिवगंगा एक्सप्रेस में सफर के दौरान खुली पोल, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का भी शक

कानपुर। सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक शातिर फर्जी रेलवे अधिकारी को पकड़ लिया गया। आरोपी संजय कुमार खुद को रेलवे मंत्रालय का अधिकारी बताकर ट्रेनों में सफर कर रहा था और यात्रियों व स्टाफ पर रौब झाड़ रहा था। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर मामला खुल गया। जानकारी के मुताबिक, आरोपी शिवगंगा एक्सप्रेस में यात्रा कर रहा था। सफर के दौरान वह खुद को रेलवे का अधिकारी बताते हुए विशेष व्यवहार की मांग कर रहा था। उसके हाव-भाव और पहचान को लेकर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को संदेह हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी गई।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

सूचना मिलते ही विजिलेंस टीम और रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय हो गए। ट्रेन के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचते ही टीम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वह अपने दावों को साबित नहीं कर सका और बार-बार जवाब बदलता रहा, जिससे शक और गहरा गया। जांच के दौरान आरोपी के पास से रेलवे मंत्रालय का एक पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसमें उसे अधिकारी दर्शाया गया था। लेकिन गहन जांच में यह आईडी पूरी तरह फर्जी पाई गई।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी कर सकता है। पुलिस अब उसके पिछले रिकॉर्ड खंगाल रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि उसने किन-किन लोगों को निशाना बनाया और कितनी रकम की ठगी की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उसके संभावित नेटवर्क और अन्य साथियों की भी जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि रेलवे में फर्जी पहचान बनाकर ठगी और धोखाधड़ी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जहां आरोपी नकली आईडी और वर्दी का इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेते हैं। ऐसे मामलों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बढ़ा रही हैं।

हाइवे पर दो बाइकों की भिड़ंत, युवती समेत चार गंभीर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में हाइवे पर सिखमापुर मोड़ पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में युवती समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सीएचसी) पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।कानपुर नगर के थाना सचेंडी क्षेत्र के भौंती गांव निवासी अभिषेक कुमार भोगनीपुर जा रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर नोनापुर गांव निवासी शोभित गुप्ता, रश्मी और रामपुर हराहरा गांव की करिश्मा सवार थे। सिखमापुर मोड़ पर दोनों बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

ई-रिक्शा में खेलते समय गिरा मासूम, हालत गंभीर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के श्याम सुंदरपुर गांव में लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा में खेलते समय 4 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और राहगीरों की मदद से बच्चे को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गांव निवासी नितिन कुमार का पुत्र शौर्य गौतम (4) घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा में खेल रहा था। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ई-रिक्शा से नीचे गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मासूम को सीएचसी भोगनीपुर पहुंचाया। जहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. आरती सिंह ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक देखते हुए बच्चे कोअस्पताल रेफर कर दिया गया।

बैंक से निकली महिला का रुपयों का बैग लेकर भागीं दो महिलायें, लोगो ने पुलिस को सौंपा

» बैंक के बाहर 'रेकी गैंग' का वार नाकाम, दो महिलाएं रंगे हाथ दबोची गईं

» रुपए निकालकर निकली महिला को बनाया निशाना, बैग छीनकर भागने की कोशिश, भीड़ व गार्ड ने दबोचा

» भीड़ और गार्ड की सतर्कता से खुला अपराध का खेल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े बैंक के बाहर लूट की कोशिश का मामला सामने आया, जहां सुनियोजित तरीके से रेकी कर रही दो महिलाओं को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना जीटी रोड स्थित खेलदार मोहल्ले की है, जहां बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकली महिला को निशाना बनाया गया।पीड़िता शबाना बेगम, जो थरियांव थाना क्षेत्र के उसरैना गांव की रहने वाली हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से अपने खाते से 39 हजार रुपये निकालने आई थीं। आरोप है कि बैंक के अंदर मौजूद दो महिलाएं पहले से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं।

जैसे ही शबाना रुपये लेकर बाहर निकलीं, दोनों महिलाओं ने मौका पाकर उनका बैग छीनने का प्रयास किया।हालांकि शबाना की सतर्कता और हिम्मत के चलते उन्होंने तुरंत पलटकर बैग वापस छीन लिया और शोर मचा दिया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और बैंक गार्ड ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर चौकी ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह कोई संगठित 'रेकी गैंग' हो सकता है, जो बैंक ग्राहकों को निशाना बनाता है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।

एआई जेनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो

किशोरियों की सेहत की ओर बड़ा कदम

9 को लगा सर्वाइकल कैंसर से बचाव का अंतिम टीका

» राज्यपाल की प्रेरणा व विश्वविद्यालय के प्रयास से निःशुल्क अभियान सफल, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता भी बढ़ी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को 79 किशोरियों को वैक्सीन की अंतिम डोज लगाई गई। यह अभियान मा. कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल की प्रेरणा तथा कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।अभियान के अंतर्गत मंधना-1 व मंधना-2 कम्पोजिट विद्यालय, होराबांगर, कुरसौली कम्पोजिट, उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरी, शंकरपुर, गंभीरपुर कछार और भजनलाल स्वतंत्र संग्राम इंटर कॉलेज, गबड़हा सहित विभिन्न क्षेत्रों की किशोरियों को अंतिम डोज निःशुल्क प्रदान की गई। टीकाकरण का कार्य जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की टीम द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ नर्स श्रीमती उषा और डॉ. अनुराग मिश्रा का विशेष सहयोग रहा।

अभियान के सफल संचालन में समन्वयक डॉ. प्रवीन कटियार की अहम भूमिका रही। वहीं वालंटियर टीम मनीष, कृतिका, मानसी, कुमुद, सागर, प्रतीक पटेल, प्रतीक मौर्य, तान्या, हर्षित गंगवार, अदनान और मानमेंद्र ने सक्रिय भागीदारी निभाई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किशोरियों में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें समय रहते सुरक्षित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के अभियान से स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक संदेश भी जा रहा है।

नकल नवीस की बदसलूकी पर भड़के अधिवक्ता

रसूलाबाद तहसील में कलमबंद हड़ताल

दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। तहसील परिसर में नकल निकलवाने गए एक अधिवक्ता के साथ कथित अभद्रता का मामला तूल पकड़ गया है। घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने शनिवार को रसूलाबाद तहसील में कलमबंद हड़ताल कर दी और सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठ गए।अधिवक्ता केके मिश्रा के अनुसार, 10 अप्रैल को वे नकल लेने के लिए तहसील में तैनात अमीन कुंती देवी, जो नकल नवीस का कार्य भी देखती हैं, के पास पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान कुंती देवी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मामले की शिकायत लेकर जब वह तहसीलदार कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद लिपिक राघव यादव और कुंती देवी ने दोबारा उनके साथ अपमानजनक

व्यवहार किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने तक की धमकी दी। अधिवक्ता रब्बानी खान ने बताया कि महिला कर्मचारी होने का फायदा उठाकर वह लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती हैं।

प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। बाद में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल तहसील सभागार पहुंचा, जहां उन्होंने अपर

जिलाधिकारी (वित्त) दुष्यंत कुमार मौर्य को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक दोषी कर्मचारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

धरने में वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार शुक्ला, ब्रजेश त्रिपाठी, विमल कुमार चतुर्वेदी, संदीप मिश्रा, आरपी राजपूत, शिवस्वरूप राजपूत, कन्हैयालाल कुशवाहा, अरुण कुमार राजपूत, अर्जुन सिंह, कपिल पांडेय, बृजेश चतुर्वेदी, घनश्याम तिवारी, दिनेश कुमार, फैजान खान, पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा, सर्वेश पाल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

माती कचहरी में चुनावी रणभेरी ढोल-नगाड़ों के बीच 27 प्रत्याशी मैदान में

» 915 मतदाता तय करेंगे किसके सिर सजेगा ताज, नामांकन के साथ तेज हुई सियासी सरगर्मी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। माती कचहरी परिसर शुक्रवार को पूरी तरह चुनावी माहौल में डूबा नजर आया। एकीकृत बार एसोसिएशन के चुनाव के तहत 27 प्रत्याशियों ने गाजे-बाजे, डीजे और समर्थकों के जुलूस के साथ नामांकन दाखिल किया। एल्डर कमेटी की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, जिससे पूरा परिसर चुनावी रणभूमि में तब्दील हो गया और हर ओर नारेबाजी गूंजती रही।

एल्डर कमेटी सदस्य गिरीश सचान के अनुसार 17 अप्रैल को विभिन्न पदों के लिए

27 नामांकन हुए, जबकि 18 अप्रैल तक प्रक्रिया जारी रहेगी। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और वापसी होगी।

इस चुनाव में 19 पदों पर मुकाबला होना है, जिसमें 915 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नामांकन शुल्क के रूप में करीब 1.70 लाख रुपये जमा हुए हैं।अध्यक्ष पद पर राधेश्याम कटियार, महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, हरिशंकर चतुर्वेदी और वीरेंद्र सिंह पाल के बीच कड़ा मुकाबला है। महामंत्री पद पर कुलदीप कुमार, अरविंद सिंह यादव, वंदना गुप्ता और मनवीर सिंह पाल मैदान में हैं। अन्य पदों पर भी कई प्रत्याशी आमने-सामने हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है।नामांकन से पहले प्रत्याशियों ने कचहरी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया, फिर जुलूस के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पर्चा दाखिल किया। समर्थकों ने फूल-मालाओं से स्वागत कर उत्साह दिखाया

। युवा प्रत्याशी आदित्य पांडेय दीपक ने अधिवक्ताओं के हितों और कोर्ट की व्यवस्थाओं में सुधार को प्राथमिकता बताते हुए जीत का दावा किया।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 4 मई को मतदान होगा और इसके बाद शपथ ग्रहण कराया जाएगा। नामांकन के साथ ही कचहरी में बैठकों और रणनीतियों का दौर तेज हो गया है। वहीं, 15 अप्रैल की हड़ताल को लेकर विवाद भी सामने आया है। माती कोर्ट अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने इसे अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होने की बात कही गई है।

अभियान कागजों में, ब्लॉक परिसर में गंदगी का राज

मैथा ब्लॉक मुख्यालय में जलभराव, कूड़े के ढेर और झाड़ियां-संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर उठे सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। कानपुर देहात में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर प्रशासन भले ही सक्रियता के दावे कर रहा हो, लेकिन मैथा ब्लॉक मुख्यालय की जमीनी तस्वीर इन दावों की पोल खोल रही है। ब्लॉक परिसर के भीतर स्थित कर्मचारी आवासों के आसपास फैली गंदगी, उगी झाड़ियां और जलभराव ने व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उजागर कर दी है।

जहां सरकारी कर्मचारी निवास करते हैं, वहीं कूड़े के ढेर सड़ रहे हैं और लंबे समय से सफाई नहीं होने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। आवासों के आसपास घनी झाड़ियां और खरपतवार यह दर्शाते हैं कि नियमित सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है।

हालात इतने खराब हैं कि कई स्थानों पर जलभराव बना हुआ है, जिससे मच्छरों के पनपने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ब्लॉक मुख्यालय के अंदर ही इस तरह की बदहाली अभियान की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रही है।पूरे मामले में एडीओ पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर सफाई कर्मियों की तैनाती और निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, लेकिन जमीनी हालात इसके उलट दिख रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह समस्या नई नहीं है। लंबे समय से शिकायतें होने के बावजूद केवल आश्वासन दिए जाते रहे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

आवासों के पीछे फैली कंटीली झाड़ियां, सड़ते कूड़े और जलभराव से उठती दुर्गंध ने यहां रहना मुश्किल कर दिया है। यह स्थिति न केवल अस्वच्छता को बढ़ा रही है, बल्कि कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुकी है।

विडंबना यह है कि यही ब्लॉक मुख्यालय पूरे क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का केंद्र है। ऐसे में यहां की बदहाली ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का अंदाजा खुद ही बयां कर रही है। अब जरूरत है कि जिलाधिकारी कपिल सिंह और सीडीओ इस मामले का तत्काल संज्ञान लें और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। खंड विकास अधिकारी संजू सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी लेकर जल्द ही सफाई अभियान चलाया जाएगा।

- ब्लॉक परिसर में कूड़े के ढेर और झाड़ियां बनी समस्या
- जलभराव से मच्छरों के पनपने का बढ़ा खतरा
- संचारी रोग अभियान की जमीनी हकीकत आई सामने
- एडीओ पंचायत की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
- शिकायतों के बावजूद अब तक नहीं हुई ठोस कार्रवाई

सपा सांसद की नेमप्लेट पर जूते-चप्पल बरसाकर भाजपा की महिलाओं का विरोध

महिला आरक्षण बिल को लेकर सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल के आवास पर घेराव, तीखी नारेबाजी से बढ़ा सियासी ताप

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी घमासान अब सड़कों तक पहुंच गया है। शनिवार को दामोदर नगर स्थित समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने सांसद के घर का घेराव करते हुए उनकी नेमप्लेट पर जूते-चप्पल बरसाकर अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचीं और सपा के खिलाफ तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध कर सपा और उसके सांसदों ने महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच उजागर की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो दल इस विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं।

महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी से भरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण का विरोध यह दर्शाता है कि सपा को महिलाओं की प्रगति से भय है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी ने कहा कि संसद में किए गए विरोध का जवाब अब जनता और विशेष रूप से महिलाएं सड़कों पर दे रही हैं।

घटना के दौरान इलाके में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के चलते हालात नियंत्रण में रहे। इस प्रदर्शन के बाद शहर का सियासी माहौल और गरमा गया है तथा आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी बयानबाजी की संभावना जताई जा रही है।

मानव एकता दिवस पर सेवा और समरसता का संगम 24 को रक्तदान शिविर

कानपुर देहात के विभिन्न निरंकारी शाखाओं में होगा रक्तदान शिविरों का आयोजन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मानवता, प्रेम और आध्यात्मिक एकत्व के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संत निरंकारी मिशन द्वारा 24 अप्रैल को 'मानव एकता दिवस' श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाएगा। यह दिवस सेवा, भाईचारे और आध्यात्मिक समरसता का प्रतीक बनकर समाज को एकसूत्र में पिरोने का कार्य करेगा।इस पावन अवसर पर जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर, शिवली और झींझक सहित विभिन्न निरंकारी शाखाओं में विशाल रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य आयोजन स्थल पर प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालु सेवा-भाव से रक्तदान करेंगे, जिसमें चिकित्सकों की टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी का सहयोग रहेगा।दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर-2 में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के सान्निध्य में भव्य सत्संग का आयोजन होगा, जहां श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति और एकत्व का अनुभव करेंगे। देश-विदेश की शाखाओं में भी श्रद्धालु इसी भाव के साथ इस दिवस को मनाएंगे। यह आयोजन बाबा गुरबचन सिंह जी और चाचा प्रताप सिंह जी की स्मृति को समर्पित है, जिनका जीवन सेवा, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देता है।संत निरंकारी मण्डल के सचिव जोगिन्दर सुखीजा ने बताया कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के मार्गदर्शन में आयोजित इन शिविरों में हजारों श्रद्धालु निःस्वार्थ भाव से रक्तदान कर मानव जीवन की रक्षा में योगदान देंगे। उल्लेखनीय है कि मिशन पिछले चार दशकों से रक्तदान जैसे सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है और इसके माध्यम से अनगिनत लोगों को जीवनदान मिल चुका है। यह पावन दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा है, जो समाज में आपसी सद्भाव और एकता की भावना को और सुदृढ़ करेगा।

श्रम कानून तोड़ने वालों पर योगी सरकार का प्रहार

203 ठेकेदारों के लाइसेंस निरस्त 1.16 करोड़ की वसूली की तैयारी

गौतमबुद्धनगर में श्रमिक हितों से खिलवाड़ पर कड़ा एक्शन, ब्लैकलिस्टिंग से लेकर मुकदमे तक की प्रक्रिया तेज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गौतमबुद्धनगर (नोयडा)। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर अब तक का सबसे सख्त संदेश दिया है। श्रम कानूनों के उल्लंघन और श्रमिकों के देय भुगतान में लापरवाही बरतने वाले 24 औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े 203 ठेकेदारों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही इन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने और बकाया धनराशि की वसूली के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

- 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई
- 1.16 करोड़ रुपये की पेनल्टी का नोटिस जारी
- लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ ब्लैकलिस्टिंग प्रक्रिया शुरू
- 21 प्रतिशत वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से लागू
- ओवरटाइम, बोनस और ग्रेच्युटी सुनिश्चित करने के निर्देश
- अवैध कटौती पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर राकेश द्विवेदी के अनुसार, हाल ही में श्रमिकों के आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और अव्यवस्था की घटनाओं की जांच में कई संविदाकारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए जहां श्रमिकों को उनके वैधानिक अधिकारों जैसे वेतन,

ओवरटाइम, बोनस और अन्य लाभ से वंचित रखा गया। इस पर विभाग ने 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार 67 रुपये की पेनल्टी का नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यह राशि श्रमिकों को तत्काल भुगतान की जाए।

श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई केवल प्रारंभिक चरण है।

शेष दोषी ठेकेदारों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का रुख स्पष्ट है श्रमिकों के अधिकारों से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसी बीच, श्रमिकों में वेतन वृद्धि को लेकर लंबे समय से चल रहे असंतोष को देखते हुए शासन स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर बड़ा निर्णय लिया गया है। गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के वेतन में 21 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और इसका भुगतान मई माह की 7 से 10 तारीख के बीच किया जाएगा। यह नई दरें संविदा और स्थायी दोनों श्रमिकों पर समान रूप से लागू होंगी।

श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के वेतन से ईपीएफ और ईएसआई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य कटौती पूरी तरह अवैध मानी जाएगी।

यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित नियोक्ता और संविदाकार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से, तथा बोनस और ग्रेच्युटी जैसे सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि वेतन भुगतान में देरी या कम भुगतान के मामलों में केवल ठेकेदार ही नहीं,

बल्कि उनके प्रधान सेवायोजक भी जवाबदेह माने जाएंगे।

इस निर्णय को श्रमिक हितों की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करेगा।

उद्यमी संगठनों की सक्रिय भूमिका

जनपद के उद्यमी संगठन भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को न्यूनतम वेतन वृद्धि और सरकारी गाइडलाइंस के पालन के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, ऑडियो-वीडियो संदेशों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। यह पहल औद्योगिक सौहार्द और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

सख्ती के पीछे सरकार का संदेश

सरकार का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी सरकार श्रम कानूनों के पालन को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम कर रही है, जिससे उद्योगों में जवाबदेही तय हो सके।

उद्योग जगत पर संभावित असर

इस कार्रवाई से औद्योगिक इकाइयों में अनुशासन बढ़ेगा, लेकिन साथ ही संविदाकारों और नियोक्ताओं पर अनुपालन का दबाव भी बढ़ेगा। इससे अल्पकाल में संचालन लागत बढ़ सकती है, पर दीर्घकाल में यह औद्योगिक स्थिरता और श्रमिक संतोष को मजबूत करेगा।

श्रमिकों के लिए क्या बदलेगा?

21प्रतिशत वेतन वृद्धि, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और अन्य वैधानिक लाभों की गारंटी से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, सख्त निगरानी से शोषण की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

सफाईकर्मियों का फूटा गुस्सा, 5 साल सेवा के बाद भी दर-दर भटकने को मजबूर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर ब्लॉक के औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में अस्थायी सफाई कर्मियों के साथ कथित अन्याय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 508 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में पहले से ही सफाई कर्मियों की कमी है, ऐसे में चार कर्मियों को काम से हटाए जाने से सफाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

» वेतन कटौती की शिकायत करने पर ठेकेदार की कार्रवाई

काम बहाली को लेकर डीएम और सीएम पोर्टल पर लगाई गुहार

- वेतन कटौती की शिकायत के बाद 4 सफाईकर्मी हटाए गए
- 5 साल से लगातार सेवा दे रहे थे सभी कर्मचारी
- डीएम को प्रार्थना पत्र के बावजूद कार्रवाई लंबित
- मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत
- काम बहाली न होने पर परिवारों के सामने संकट

मामले के अनुसार, औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) सतहरिया में कार्यरत चार अस्थायी सफाईकर्मियों–ललित सिंह, राहुल कुमार सरोज, रजित राम और संजय कुमार मिश्रा–ने ठेकेदार पर वेतन भुगतान में कटौती का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र से लिखित शिकायत की थी। आरोप है कि उनका वेतन सीधे खाते में न आकर ठेकेदार के माध्यम से आता था, जिसमें पूरी राशि नहीं दी जाती थी।शिकायत के बाद ठेकेदार ने नाराज़ होकर इन कर्मियों को काम से हटा दिया। कर्मियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है और उन्हें बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से वंचित कर दिया गया। उन्होंने डीएम को पुनः प्रार्थना पत्र देकर काम बहाली की मांग की, जिस पर संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए गए, लेकिन चार दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।इससे आक्रोशित सफाईकर्मियों ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पिछले पांच वर्षों से वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब अचानक बेरोजगार कर दिए जाने से उनके परिवारों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।कर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें जल्द से जल्द काम पर वापस लिया जाए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला और व्यापक विरोध का रूप ले सकता है। सतहरिया का यह मामला न सिर्फ श्रमिक अधिकारों की अनदेखी को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि शिकायत करने वाले कर्मचारियों को किस तरह प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी तेजी और निष्पक्षता से कदम उठाता है।

परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण पर टकराव, नोटिस चस्पा, बेदखली की आहट से भड़का विरोध

» पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई तेज, 100 साल पुराने घरों पर संकट

» स्थानीय लोग बोले 'पहले 13 मीटर का वादा निभाओ'

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण ने अब रफ्तार के साथ विवाद भी पकड़ लिया है। नाका क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक मकान और दुकानें इस परियोजना की जद में आ गई हैं। पीडब्ल्यूडी ने प्रभावित भवनों पर नोटिस चस्पा कर 10 दिन में मालिकाना कागजात जमा करने का अल्टीमेटम दे दिया है, अन्यथा खाली कराने की चेतावनी दी गई है।

नोटिस के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है। सड़कों पर विरोध शुरू हो गया है और लोग सरकार से पुराना 13 मीटर चौड़ीकरण ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। कई परिवारों का दावा है कि वे एक सदी से अधिक समय से यहां रह रहे हैं, ऐसे में अचानक बेदखली उनके लिए जीवन संकट बन सकती है। सरकार जहां धार्मिक मार्गों के विकास को प्राथमिकता दे रही है, वहीं जमीन पर बसे लोगों का सवाल है विकास होगा, लेकिन क्या उनके सिर से छत हटाकर? मामला अब संवेदनशील होता जा रहा है, प्रशासन के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं।

अयोध्या में निशानेबाजी का जलवा

1470 में से 600 खिलाड़ी प्री-स्टेट के लिए क्वालीफाई

डाभासेमर स्टेडियम में चार दिवसीय प्रतियोगिता का समापन, अगस्त में दिल्ली में दिखेगा हुनर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। डाभासेमर स्टेडियम में आयोजित 29वीं यूपी प्री-स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता का शुक्रवार को सफल समापन हो गया। चार दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 36 जिलों से आए 1470 खिलाड़ियों ने भाग लिया,

जिसमें से 600 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री-स्टेट के लिए क्वालीफाई किया।समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राममंदिर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह, एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, प्रवीण यादव और यूपी रायफल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम सिंह यादव मौजूद रहे। विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

हालांकि 13 अप्रैल को सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के चलते मुकाबले नहीं हो सके, लेकिन इसके बाद प्रतियोगिता ने रफ्तार पकड़ी। 15 अप्रैल को सर्वाधिक 700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोच शनि वर्मा के अनुसार, चयनित खिलाड़ी अब अगस्त में दिल्ली में आयोजित स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

सफलता: अयोध्या के लाल उत्कर्ष सिंह बने आरबीआई में मैनेजर

उदया पब्लिक स्कूल से निकला होनहार, बीआईटीएस पिलानी से इंजीनियरिंग, एंटीएसई व केवीपीवाई स्कॉलर ने रचा इतिहास

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या के लिए गर्व का क्षण है। उदया पब्लिक स्कूल के पूर्व छात्र उत्कर्ष सिंह का चयन देश के शीर्ष वित्तीय संस्थान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंधक पद पर हुआ है। उत्कर्ष वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे बैंक ऑफ अमेरिका और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर एवं असिस्टेंट मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

उन्होंने कक्षा 12 तक की शिक्षा अयोध्या के उदया पब्लिक स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद प्रतिष्ठित संस्थान बीआईटीएस पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उत्कर्ष सिंह की उपलब्धियां यहीं नहीं रुकतीं वे एंटीएसई स्कॉलर और केवीपीवाई फेलो भी रह चुके हैं, जो उनकी मेधा और परिश्रम का प्रमाण है। उनकी इस सफलता से न केवल उनके परिवार और विद्यालय में हर्ष का माहौल है, बल्कि पूरे अयोध्या जनपद का मान भी बढ़ा है।

नाकेबंदी बरकरार, डील के दावे तेज, अमेरिका-ईरान वार्ता के दूसरे दौर पर टिकी दुनिया की नजर

होर्मुज पर 'नरमी' या रणनीतिक विराम?

स्वराज इंडिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया की सियासत में इन दिनों तेज़ी से बदलते घटनाक्रम ने वैश्विक स्तर पर उम्मीद और आशंका दोनों को जन्म दिया है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर नरमी के संकेत सामने आए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी उलझी हुई है। एक ओर ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता खोलने के दावे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका की नाकेबंदी अब भी जारी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को 'पीस प्रेसिडेंट' बताते हुए समझौते को बेहद करीब बताया है, जबकि तेहरान ने कई अहम मुद्दों पर अभी भी सख्त रुख कायम रखा है।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और समुद्री ट्रैकिंग रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने सीमित रूप से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही की अनुमति दी है। इससे तेल टैंकरों की आवाजाही में कुछ राहत जरूर दिखी है। हालांकि, अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और सुरक्षा जांच अब भी जारी है, जिससे यह साफ है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह 'पूर्ण खुलापन' नहीं बल्कि एक 'कंट्रोल्ड ओपनिंग' है यानी तनाव कम करने का संकेत, लेकिन पूरी तरह भरोसे का माहौल अभी दूर है।

अमेरिका की नाकेबंदी अब भी कायम: संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम समझौते से पहले वह ईरान पर लगाए गए आर्थिक और समुद्री प्रतिबंध नहीं हटाएगा। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार, यह दबाव बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि ईरान परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर समझौते के लिए मजबूर हो। पेंटागन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी नेवी अभी भी होर्मुज में सक्रिय है और समुद्री माइन्स हटाने के ऑपरेशन जारी हैं। इसका उद्देश्य जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन यह भी संकेत देता है कि खतरा पूरी तरह टला नहीं है।

आगे क्या होगा?

आने वाले दिनों में तीन संभावनाएं सबसे अहम हैं।

आंशिक समझौता: होर्मुज खुला रहेगा, लेकिन प्रतिबंध जारी

पूर्ण डील: यूरेनियम पर समझौता और प्रतिबंध हटना

फिर तनाव: बातचीत विफल होने पर सैन्य गतिविधि बढ़ सकती है

होर्मुज खुलना, रणनीति या मजबूरी?: होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल सप्लाई का करीब 20त्न रास्ता है। ऐसे में इसका खुलना केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक फैसला है। ईरान का यह कदम अंतरराष्ट्रीय दबाव और आर्थिक जरूरतों का मिश्रण माना जा रहा है।

ट्रंप का 'पीस प्रेसिडेंट' नैरेटिव: ट्रंप का खुद को शांति का नेता बताना राजनीतिक रणनीति भी हो सकता है। अमेरिका में चुनावी माहौल को देखते हुए यह बयान घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करता है। हालांकि, जमीनी स्तर पर नाकेबंदी जारी रहना उनके दावे पर सवाल खड़े करता है।

यूरेनियम सबसे बड़ी बाधा: ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही इस पूरे विवाद की जड़ है। जब तक इस पर ठोस समझौता नहीं होता, तब तक कोई भी शांति समझौता अधूरा रहेगा। यही मुद्दा हर बातचीत को अटका देता है।

ईरान का रुख: यूरेनियम पर समझौता नहीं

तनाव का सबसे बड़ा कारण अब भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। विशेष रूप से एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच गहरी असहमति बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम कार्यक्रम को सीमित करे जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है। तेहरान ने स्पष्ट किया है कि वह दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि शांति वार्ता की राह अब भी जटिल बनी हुई है।

सोमवार को दूसरे दौर की बातचीत

कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत सोमवार को होने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि सीमित है, लेकिन दोनों पक्षों की गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि बैक-चैनल डिप्लोमेसी तेज हो चुकी है। पहले दौर की वार्ता में ठोस परिणाम नहीं निकले थे, लेकिन इस बार होर्मुज को लेकर नरमी के संकेत बातचीत को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं।

ट्रंप का दावा: 'डील बेहद करीब'

डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता 'बहुत करीब' है और अब कोई बड़ी बाधा नहीं बची है। उन्होंने खुद को 'पीस प्रेसिडेंट' बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य युद्ध नहीं, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करना है। हालांकि, ट्रंप के इन दावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों में मतभेद है। कई विशेषज्ञ इसे कूटनीतिक दबाव की रणनीति मानते हैं, जबकि कुछ इसे वास्तविक प्रगति का संकेत मान रहे हैं।

पूरी शांति नहीं बल्कि 'नियंत्रित तनाव'

पश्चिम एशिया में फिलहाल जो दिख रहा है, वह पूरी शांति नहीं बल्कि 'नियंत्रित तनाव' की स्थिति है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन जब तक अमेरिका-ईरान के बीच मूल मुद्दों विशेषकर यूरेनियम और प्रतिबंध पर सहमति नहीं बनती, तब तक यह राहत अस्थायी ही मानी जाएगी। दुनिया की नजर अब सोमवार की संभावित वार्ता पर है यही तय करेगा कि यह नरमी स्थायी शांति में बदलती है या फिर एक और अस्थायी विराम साबित होती है।

दिनदहाड़े बैंक में धावा: फायरिंग कर 14.5 लाख कैश व 7 किलो सोना लूटा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

सिंगरौली/मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई बैंक डकैती ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में करीब साढ़े 12 बजे पांच हथियारबंद बदमाश घुसे और महज 15 से 20 मिनट के भीतर 14.50 लाख रुपये नकद और लगभग सात किलो सोना लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाई, जिससे बैंक में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक सहम गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। एक आरोपी गेट पर निगरानी करता रहा, जबकि चार अंदर घुसकर सीधे कैश काउंटर और

➪ सिंगरौली के बैढ़न में बेखौफ बदमाशों का तांडव, बिना गार्ड बैंक बना आसान निशाना

लॉकर की ओर बढ़े। उन्होंने कैशियर, मैनेजर और ग्राहकों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया और विरोध करने पर मारपीट भी की। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बैंक में उस समय कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिससे बदमाशों को वारदात को अंजाम देने में आसानी मिली।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी

घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपियों की तलाश के लिए चार से अधिक विशेष टीमें गठित की गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज में पांचों बदमाश बिना नकाब के नजर आए हैं, जो दो बाइकों पर सवार होकर फरार हुए। पुलिस को आशंका है कि आरोपी स्थानीय नहीं हैं और किसी बाहरी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर पूछताछ तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों और सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान भी जारी है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी भोपाल से सिंगरौली के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है और बैंकिंग सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com